पाक को झटका

दिनया का शायद ही कोई ऐसा मंच हो, जहां कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को मुंह की न खानी पड़ी हो। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के भारत सरकार के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान पिछले एक महीने में संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका सिहत कई देशों की शरण में जा चुका है और कश्मीर मुद्दे पर समर्थन हासिल करने की कोशिशें करता रहा है। मगर उसे सब जगह से निराशा ही हाथ लगी है। हाल में मालदीव जैसे छोटे-से देश में भी पाकिस्तान को ऐसा ही झटका लगा। मालदीव में दक्षिण एशियाई देशों के स्पीकरों के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने कश्मीर का मसला उठाया. लेकिन उसे कोई तवज्जो नहीं मिली, बल्कि सम्मेलन के बाद जारी माले घोषणापत्र में भी कश्मीर पर पाकिस्तान के सारे दावों को खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए यह एक और बड़ी कूटनीतिक हार है। यह इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर मसले पर अब दुनिया के राष्ट्र भारत के रुख का समर्थन कर रहे हैं।

पहली बात तो यह कि माले के शिखर सम्मेलन में कश्मीर मुद्दा उठाने का कोई औचित्य ही नहीं था। यह सम्मेलन दक्षिण एशियाई देशों की संसद के सदनों के अध्यक्षों का था और इसका मूल विषय सतत विकास था। लेकिन पाकिस्तान के प्रतिनिधि यहां भी बाज नहीं आए और विकास के मूल विषय से हटते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इस पर भारत ने कड़ा प्रतिकार किया और संबंधित देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस पर कड़ी आपित्त की। सदस्यों का कहना था कि इस मंच से कश्मीर का मसला इस मंच से नहीं उठाया जा सकता। मालदीव की संसद के अध्यक्ष ने तो साफ कहा कि इस फोरम पर किसी देश के अंदरूनी मामले को नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के बीच जो संवाद हुआ है उसे कार्यवाही से निकाल दिया गया और इसी वजह से घोषणापत्र में भी कश्मीर मसले पर कुछ नहीं कहा गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही कूटनीतिक नाकामी से पाकिस्तान का तिलमिलाना स्वाभाविक है। कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण कर पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण और भारत के खिलाफ झूठा प्रचार पाकिस्तान सरकार की रणनीति का हिस्सा अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद कह चुके हैं कि उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दुनिया के तमाम मुल्कों में जा–जाकर उनके राष्ट्र प्रमुखों से मिलेंगे और बताएंगे कि कश्मीर में भारत क्या कर रहा है। इसी रणनीति के तहत पिछले एक महीने में पाकिस्तान ने इस्लामी देशों सहित कई देशों से कश्मीर पर समर्थन मांगा। लेकिन उन्हें हाथ कुछ नहीं लगा। यहां तक कि इस्लामी देशों के संगठन तक से कोई भरोसा या मदद के संकेत नहीं मिले। किसी देश ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के भारत के फैसले को गलत नहीं बताया बल्कि साफ कहा कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। सवाल है कि ऐसे में पाकिस्तान करे तो क्या करे। शाह महमूद कुरैशी तो पाक अधिकृत कश्मीर में एक जनसभा में इस हकीकत को स्वीकार कर चुके हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया के मुल्कों का समर्थन मिलना आसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस सच्चाई से मुंह मोड़ रही है और अपनी अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है।

शहर में बुजुर्ग

भिक्षिणी दिल्ली की एक संभ्रांत कॉलोनी में रह रहे एक इक्यानबे वर्षीय बुजुर्ग की जिस तरह उनके नौकर ने ग्ला दबा कर हत्या कर दी और फिर लाश को फ्रिज में डाल कर ठिकाने लगाने का प्रयास किया, वह न सिर्फ राजधानी में बढ़ते अपराध, बल्कि शहरों में रह रहे बुजुर्गों की असुरक्षा को भी रेखांकित करता है। यह बुजुर्ग दंपति ग्रेटर कैलाश के एक मकान में किराए पर रह रहा था। उनके घरेलू सहायक ने दोनों को रात के भोजन में कोई नशीली दवा दे दी और बेहोश होने के बाद पित की गला दबा कर हत्या कर दी। बुजुर्ग दंपित का एक बेटा आस्ट्रेलिया में रहता है, जबकि दूसरा बेटा इसी शहर में अपना कारोबार करता और माता-पिता से अलग रहता है। महानगरों में यह विडंबना नई नहीं है कि बहुत सारे बुजुर्ग अपनी संतानों की उपेक्षा का शिकार हैं। इस वजह से कई लोग वृद्धाश्रमों में रहने को मजबूर हैं, तो कई घरेलू सहायकों के सहारे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जिन बच्चों को मां-बाप पढ़ा-लिखा कर योग्य बनाते हैं, वही बुढ़ापे में उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं, संवेदना का इस तरह कुंद होते जाना बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे ही उपेक्षित लोगों में से कुछ अपने लोभी सहायकों की साजिशों का शिकार हो जाते हैं।

दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा का सवाल पुराना है। इस तरह वृद्धों की हत्या के अनेक उदाहरण हैं। कई मामलों में उनके रिश्तेदार ही संपत्ति आदि हड़पने की मंशा से उनकी हत्या कर देते हैं। कई बार लूट की वारदात भी हो चुकी है। घरेलू सहायक भी घर का सामान लूटने के मकसद से अपने दोस्तों के साथ मिल कर ऐसा कर देते हैं। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने संभ्रांत इलाकों में अलग से गश्त शुरू की थी। पड़ोसी निगरानी योजना चलाई थी। अकेले रह रहे बुजुर्गों के घरों में आपात घंटी की व्यवस्था की गई थी, जिसे बुजुर्ग दबाएं तो सीधे थाने में सूचना पहुंचे। अब तो जगह-जगह कैमरे यानी सीसीटीवी लगाए गए हैं। मोबाइल फोनों में ऐसे ऐप्प हैं, जिनके इस्तेमाल से महिलाएं और बुजुर्ग आपातकाल में सीधे पुलिस थाने को सूचना भेज सकते हैं। घरेलू सहायकों की पहचान दर्ज कराने का नियम भी है। फिर भी बुजुर्गों की सुरक्षा की कोई गारंटी सुनिश्चित नहीं कराई जा सकी है। ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई ताजा वारदात इसका एक उदाहरण है।

महानगरों में युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति पुलिस और समाज के लिए चिंता का विषय है। इसकी कुछ वजहें साफ हैं। संचार माध्यमों पर अपराध की घटनाओं को कुछ अधिक जगह मिलने लगी है, फिर सोशल मीडिया के आने से आपराधिक घटनाओं के नाट्य रूपांतरण खूब उपलब्ध होने लगे हैं। महानगरों में सुख-सुविधा वाली और ऐशो-आराम की जिंदगी जीने की ख्वाहिश युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ी है। वे आसानी से धन अर्जित करने की तरकी बें सोचते रहते हैं। ऐसे में वे लूटपाट और हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। आसानी से धन अर्जित करने की योजनाएं बनाने में संचार माध्यमों पर उपलब्ध आपराधिक घटनाओं के नाटकीय रूपांतर उनकी मदद करते हैं। बुजुर्ग चूंकि अक्सर अशक्त होते हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाना बहुत आसान होता है। ग्रेटर कैलाश के घरेलू सहायक की भी आसानी से धन अर्जित करने की लालसा को इन्हीं नाट्य रूपांतरों और आपराधिक घटनाओं की प्रस्तुतियों ने पंख दिए होंगे। महानगरों में बुजुर्गों की हिफाजत पर अभी और गंभीरता से सोचने की दरकार है।

कल्पमेधा

जातियां व्यक्तियों से बनती हैं लेकिन राष्ट्र का निर्माण केवल संस्थाओं द्वारा होता है। –डिजराइली

एनआरसी से निकलते सवाल

संजीव पांडेय

एनआरसी की अंतिम सूची आ गई है। कानूनी दावपेंच और राजनीति अब शुरू होगी। एनआरसी को अंतिम रूप दिए जाने की कार्यशैली पर सवाल उटे हैं। इस सूची में महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज करने के आरोप भी लगे हैं। जिन 19.06 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया है, उनमें से लाखों लोगों के पास वैध दस्तावेज थे, लेकिन उन्हें एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। सवाल असम सरकार के महत्त्वपूर्ण लोगों ने ही उढाया है।

37सम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रर (एनआरसी) की अंतिम सूची जारी हो गई है। इसके साथ ही भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। अंतिम सुची से उन्नीस लाख लोग बाहर हो गए हैं। एनआरसी में शामिल होने के लिए 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। पिछले साल जारी सुची में चालीस लाख लोगों को बाहर किया गया था। इसमें से बाहर किए लोगों ने अपना पक्ष रखा, इसके बाद अब अंतिम सूची आ गई। अंतिम सूची में इक्कीस लाख लोग और जुड़ गए और उन्नीस लाख लोग बाहर रह गए। बाहर हुए लोगों को अपने भारतीय नागरिकता संबंधी दावे के लिए विदेशी पंचाट में अपील करनी होगी। एनआरसी से बाहर किए गए लोगों के पास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील करने का भी अधिकार होगा।

एक अहम सवाल यह भी है कि जिन लोगों का नाम अंतिम सूची में नहीं है, उनका क्या किया जाएगा।

क्या उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा? क्या वर्तमान परिस्थितियां भारत को यह अनुमित देती हैं कि जो लोग विदेशी घोषित हो चुके हैं, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए ? दक्षिण एशिया में भारत की कुछ मजबूरियां हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहां पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने साफ कहा था कि राष्टीय नागरिक रजिस्टर से निकाले गए लोगों का मामला भारत का आंतरिक मामला है। इसका बांग्लादेश से कुछ लेना देना नहीं है। जयशंकर ने यह बात बांग्लादेश के विदेश मंत्री से बैठक के बाद कही थी। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश के गृह मंत्री भारत आए थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी। लेकिन उस दौरान दोनों तरफ से कोई साझा बयान नहीं आया था। तब यह अंदेशा जताया गया था कि दोनों मुल्कों के बीच महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ विवाद है, जिसमें भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों का मसला भी

शामिल है। हालांकि पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश के दौरे पर गए भारत के तत्कालीन गृह मंत्री ने बांग्लादेश सरकार को साफ कहा था कि बांग्लादेश निश्चिंत रहे, एनआरसी से निकाले गए लोगों को वापस बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। बांग्लादेश खुद इस समय रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में वह भारत से वापस भेजे गए लोगों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। फिर, भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक अवैध नागरिकों को वापस भेजने को लेकर कोई संधि भी नहीं है।

पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से खराब संबंध झेल रहा भारत बांग्लादेश को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। इसके आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक कारण हैं। भारत ने

विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कश्मीर मसले अंतराष्ट्रीयकरण करने में लगा है। इस स्थिति में भारत को मुसलिम बहल देश बांग्लादेश का समर्थन हासिल करना जरूरी है। बांग्लादेश इस समय एक उभरती आर्थिक शक्ति है। उसकी जीडीपी विकास दर आठ प्रतिशत है। बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी भी 1888 अमेरिकी डॉलर है, जो भारत से थोड़ा ही कम है। कई और कारणों से भी बांग्लादेश भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। बांग्लादेश में उर्जा, सड़क, दूरसंचार, रेल आदि क्षेत्र में विकास की काफी संभावना है और वहां भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है। यही नहीं, दक्षिण-पूर्व

एशिया से भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत को चीन का भी डर है। बांग्लादेश से संबंध खराब होने की स्थिति में वह चीन के नजदीक जा सकता है। चीन ने 'बेल्ट एंड रोड' पहल के तहत 2016 में चीन-बांग्लादेश संबंधों को नई दिशा दी है। इसके तहत चीन ने बांग्लादेश में अड़तीस अरब डालर के निवेश की योजना बनाई है। आज बांग्लादेश कपडा उद्योग में काफी आगे निकल चुका है। यह दुनिया का दुसरा बड़ा रेडीमेड कपड़े का निर्यातक बन गया है। ऐसे में भारत बांग्लादेश की उभरती हुई अर्थव्यस्था को नजर अंदाज नहीं कर सकता है। इन परिस्थितियों में भारत किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रर से निकाले गए लोगों को वापस बांग्लादेश भेजने की जिद नहीं करेगा। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या पर



हाल में अनुच्छेद 370 हटा कर जम्मू-कश्मीर का हमेशा राजनीति होती रही है। 2003 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री ने भारत में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या दस लाख के करीब बताई थी। लेकिन नवंबर 2016 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने इनकी संख्या दो करोड बताई थी। अब अगर एनआरसी के आंकडों को देखें तो असम में उन्नीस लाख अवैध नागरिक हैं, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। आंकड़ों में ये भिन्नता साफ करती है कि भारत सरकार के पास कोई सही आंकडा भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को लेकर नहीं है। हालांकि अब समय बदला है। बांग्लादेश की अच्छी होती आर्थिक स्थिति ने बांग्लादेशियों को बेहतर रोजी-रोटी का विकल्प

बांग्लादेश से ही मुहैया करवा दिया है। इससे भारत में होने वाली अवैध घुसपैठ की संख्या कम हुई है।

एनआरसी की अंतिम सूची आ गई है। कानूनी दावपेंच और राजनीति अब शुरू होगी। एनआरसी को अंतिम रूप दिए जाने की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। इस सूची में महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज करने के आरोप भी लगे हैं। जिन 19.06 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया है, उनमें से लाखों लोगों के पास वैध दस्तावेज थे, लेकिन उन्हें एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। सवाल असम सरकार के महत्त्वपूर्ण लोगों ने ही उठाया है। अंतिम सूची को चुनौती देने की तैयारी हो गई है, क्योंकि चार से पांच लाख लोगों को भारतीय नागरिक साबित करने वाले जरूरी दस्तावेजों को एनआरसी ने रिकार्ड में नहीं लिया। इसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीडन के कारण भारत आए थे। चंकि उस समय

> बांग्लादेश बना नहीं था और धार्मिक आधार पर पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ काफी भेदभाव था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग भाग कर भारत में आ गए थे। लाखों आवेदकों के पास उस समय जारी किया गया शरणार्थी प्रमाणपत्र मौजूद है। ये प्रमाणपत्र जमा भी करवाए गए, लेकिन उन्हें संज्ञान मे नहीं लिया गया। अब ये लोग विदेशी न्यायाधिकरण में जाने की तैयारी में हैं।

दरअसल, एनआरसी मसुलिम विरोधी नहीं बिल्क बांग्ला विरोधी है। बेशक इसे धार्मिक रंग देकर राजनीति होती रही है, लेकिन अभी निकाले गए उन्नीस लाख लोगों में हिंदुओं की संख्या काफी है। दरअसल, एनआरसी की अंतिम सूची से कोई पक्ष ख़ुश नहीं है। जो विदेशी घुसपैठियों को निकाले जाने की लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, वे नाराज हैं। क्योंकि एनआरसी से निकाले जाने

वालों की संख्या उनकी उम्मीद से काफी कम है। जबिक निकाले गए पक्ष का कहना है कि आवेदन के बाद जांच की पूरी प्रक्रिया ही खामियों भरी है। उन लाखों लोगों का नाम एनआरसी से निकाल दिया गया जिनके पास भारत की नागरिकता साबित करने के दस्तावेज मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय में एनआरसी के मुल आवेदक असम पब्लिक वर्कस ने उन्नीस लाख लोगों को एनआरसी से निकाले जाने को मजाक करार दिया है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का तर्क है कि एनआरसी से निकाले जाने वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। वहीं, ऑल असम माइनोरिटी स्टूडेंट यूनियन बहुत सारे भारतीय नागरिकों को विदेशी घोषित करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल है कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं, यह एनआरसी से कैसे तय हो पाएगा?

सोंदर्यीकरण और रोटी

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

चिछले दिनों हमारे शहर का रंगोरूप अचानक निखर गया। बरसात की फुहारों का जादू मात्र होता तो सिर्फ सड़कें धुली-धुली लग रही होतीं। पर असल में जादू शहर के प्राधिकरण का है जिसकी बदौलत सड़कें पहले से दोगुनी चौड़ी लग रही हैं। जिन फुटपाथों पर कल तक फल-सब्जियों की रेहड़ियों और पान-बीड़ी-गुटके की गुमटियों की भरमार से पैदल चलना दूभर था, आज वे खाली थीं। फुटपाथ वाली साग-सब्जी की दुकानों द्वारा बिखराया कचरा और प्लास्टिक थैलियां अचानक अंतर्ध्यान हो गई हैं। किसने घुमा दी यह जादू की छड़ी? किसने शहर के छोटे-छोटे पटरी वाले दुकानदारों को अचानक जिम्मेदार नागरिक बना दिया! जरूर वे अब प्राधिकरण द्वारा निर्मित अधिकृत दुकानों में चले गए होंगे। अपनी वातानुकूलित कार की पिछली सीट पर बैठ कर मैं अखबार में खोया ही रह जाता यदि सड़कों पर बिखरा हुआ सूनापन मुझे पहले बहुत सुंदर, फिर कुछ अजीब और अंत में भयावह न लगने लगा होता।

अचानक इन सूनी सड़कों के बाद लेबर-चौक

चौराहा आ गया। रियल एस्टेट सेक्टर का गुब्बारा फुटने के बाद से दिहाड़ी मजदुरों की जमात इस चौराहे पर दिखने लगी थी। उस गुब्बारे के फूटने की आवाज अब उन लाखों लोगों की उच्छवास में डूब चुकी है जो नीले आसमान के नीचे एक छत की कामना में जीवन भर की कमाई गंवा कर बैंकों के कर्जदार बन गए हैं। लाखों अधबने गगनचुंबी रिहायशी अपार्टमेंटों में पसरा सन्नाटा अब लेबर

चौक में जमा भारी भीड़ के बीच गुंज रहा था।

अचानक मेरी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह दो साल पहले स्थानीय गोल्फ क्लब में मेरा कैडी था। एक दिन उसने बडे उत्साह से बताया था कि उसे मानेसर में एक कार बनाने वाले कारखाने में नौकरी मिल गई। बिना कोई कौशल अर्जित किए दसवीं तक की पढ़ाई का नतीजा थी यह अकुशल श्रमिक की नौकरी। फिर भी वह बहुत उत्साहित था। आज उसे इस लेबर चौक पर देख कर आश्चर्य हुआ। पूछने पर उसने अपनी कहानी बयां कर दी। छह महीने पहले कारखाने ने मंदी की चपेट में आकर छंटनी कर दी थी। लेकिन नोएडा के एक पुराने साथी ने उसे एक एक्सपोर्ट यूनिट में काम दिला दिया था। जल्दी ही वह यनिट भी मंदी की चपेट

में आ गई। बेकारी के दिनों में ही सारी बचत गांव भेजनी पड़ गई थी जहां पिता बारिश में ध्वस्त घर की मरम्मत के लिए सहायता की गृहार लगाए हुए थे।

पिछले दिनों अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियों ने सभी का ध्यान जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर केंद्रित कर रखा था। देश की आजादी का अखंडता से नाता जुड़ते देख कर सबके मन में देशभिक्त की लहर दौड़ गई थी। इस जोशोखरोश के बीच देश की

दुनिया मेरे आगे डावांडोल आर्थिक स्थिति से केवल वे रूबरू हो पा रहे थे जिनके ऊपर मंदी का कहर सबसे पहले बरपा हुआ था। मेरे जैसों के लिए तो महंगी गाडियों का घर से निकलते ही भयंकर जाम में फंस जाना देश की जबर्दस्त तरक्की का जीता जागता प्रमाण था। धीरे-धीरे आर्थिक मंदी का भी जिक्र होने लगा जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया था। यह जरूर सोचा था कि पार्किंग की तंगी और जाम से निपटने के लिए निजी कार की अपेक्षा ओला-ऊबर जैसी टैक्सी सेवाएं

अधिक सुविधाजनक होंगी। तब कहां सोचा था कि

कुछ महीनों के अंदर ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र के साढ़े

तीन लाख कामगारों पर सेवा समाप्ति की गाज गिरेगी

और इस सुनामी को रोका न गया तो दस लाख से

सेक्टर के साथ-साथ बड़े कारखानों को कल-पूर्जे, स्टील और पेंट आदि माल मृहैया कराने वाले छोटे से लेकर भारी उद्योग भी मंदी की चपेट में आएंगे। देश की भारी भरकम समस्याओं से ध्यान हटा

भी अधिक नौकरियां दम तोड़ देंगी। ऑटोमोबाइल

कर मैंने उससे पूछा 'तो अब? क्या दिहाड़ी मजदूरी के अलावा और कोई उपाय नहीं?' वह कातर होकर बोला-'था न साहेब। कर्ज लेकर एक फलों की रेहड़ी लगाई थी। पिछले हफ्ते कमेटी वाले उसे जब्त करके ले गए।

मैं स्तब्ध हं। आर्थिक मंदी से लड़ते उद्योगों को सरकार शायद रिजर्व बैंक से एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ की थैली पाने के बाद राहत दे सकेगी। लेकिन हमारे प्राधिकरण ने जिन सात सौ दुकानों को बनवाने की घोषणा की और उन्हें आबंटित करने के पहले ही उससे सौ गुना से भी अधिक बेसहारा गरीबों को फुटपाथों से हटा दिया, उन तक यह राहत कब पहुंचेगी! मेरी धुंधलाती आंखों के सामने अखबार में छपी मोबाइल और चेन आदि झटकने की खबरें और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेकसूर सैन्य बलों पर बम फेंकते आतंकियों की तस्वीरें नाच रही हैं। मैं सोच रहा हूं फुटपाथों और सड़कों की सुंदरता ज्यादा जरूरी थी या इन जैसों के लिए रोटी।

मंदी की मार

रोश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। 💙 अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्र संकट का सामना कर रहे हैं। आर्थिक सुस्ती के चलते जीडीपी वृद्धि दर पांच फीसद रह गई है। विनिर्माण क्षेत्र की दर आधा फीसद रह गई है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर दो फीसद रह गई है। देश के सार्वजनिक बैंक घाटे में हैं। उत्पादित वस्तुओं की मांग में कमी के कारण कंपनियों का कारोबार ठप हो गया है और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। हालात देख कर लगता है कि सरकार इस अप्रत्याशित मंदी से अनिभज्ञ थी, इसलिए इन मुश्किलों से निपटने की को तैयारी नहीं थी। अब आनन-फानन में बड़े फैसले किए जा रहे हैं। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह मंदी अचानक नहीं आई, बल्कि सरकार द्वारा पिछले वर्षों में किए गए गलत आर्थिक फैसलों के कारण ऐसा हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदम आम व्यापारियों के लिए मारक साबित हुए। सरकार को चाहिए कि पिछली गलतियों से सबक लेकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योग्य अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की सलाह मानते हुए कदम उटाने चाहिए।

• निशांत महेश त्रिपाठी, कोंढाली (नागपुर)

संकट में जाधव

अंतरराष्ट्रीय अदालत के दबाव में पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को राजनियक पहुंच देने को बाध्य हुआ। तीन साल की प्रतीक्षा के बाद भारत के उपउच्चायुक्त कुलभूषण से मिले। लेकिन जो बातें सामने आई हैं वे चिंताजनक ही हैं। कुलभूषण की बातों से लग रहा है वह पाकिस्तानी दबाव में है और वहीं बोल रहा है जो पाकिस्तानी अधिकारी चाहते हैं। हालांकि यह तो होना ही था। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी की गई। ऐसे में उसे मालूम है कि कुछ कर रहा है। जो अधिकारी भी इस परियोजना में को लेकर आवाज उठानी होगी ताकि एनआरसी में रहना है। कुलभूषण मामले में आइसीजे ने पिछले जुलाई में जो फैसला दिया था उसे पूरा न्याय तो नहीं कहा जा सकता। क्या पाकिस्तान की सैन्य या सिविल अदालतों से जाधव को न्याय मिल सकेगा? जबिक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सजा देने वाला जज यह कह चुका है कि उसने दबाव में आकर सजा सुनाई थी। ऐसे में कुलभूषण का क्या होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

देर में भारतीय दूत तो उसके पास से चले जाएंगे। शामिल रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान या चीन से आए फिर सुधार किए जाएं और असल नागरिक को उसके बाद उन्हें तो पाकिस्तानियों की कैद में ही हुए लोग नहीं हैं, यही के हैं। इन पर सख्त कार्रवाई उसका अधिकार दिया जाए। होनी चाहिए। इसी देश का नमक खाने वाले लोग विकास निर्माण में इस प्रकार की सेंध लगाएंगे तो देश की क्या हालत होनी है! सोचा जा सकता है।

• हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद (उज्जैन)

नागरिकता पर सवाल देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

एनआरसी) पर फिर सवाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-८, सेक्टर-7, नोएडा २०१३०१, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

निकट भविष्य में तो कुलभूषण के पाकिस्तान के चुंगल से छूटने के आसार दिखाई नहीं देते। जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी (जमशेदपुर)

भ्रष्टाचार का नतीजा

झारखंड की कोनार नदी पर सिंचाई परियोजना शुरू हुई थी, जिसे पूरा होने में बयालीस साल का समय लग गए। फिर कोढ़ में खाज यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा परियोजना का उद्घाटन करने के महज चौदह घंटे के अंदर ही यह परियोजना ढह गई। इससे पैंतीस गांव की फसलें पानी में डूब कर तहस-नहस हो गई। इस घटना से जाहिर होता है कि देश में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कि क्या दशा है? भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का दीमक राष्ट्र को पूरी तरह से जर्जर

रहे हैं। इतने बड़े और जरूरी काम में इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो सकती है कि ज्यादातर लोगों के नाम ही गायब हैं? यह एक चिंता का विषय है। इसको तो सीधा पैंसे और समय की बर्बादी कहेंगे। जो संस्था एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई उस तक ने आंकडों में फेरबदल की शिकायत है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) भी इसके विरोध में बोल रहा है। भाजपा और कांग्रेस भी इससे अछूते नहीं रहे और एनआरसी पर सवाल उठा रहे हैं।

क्या यह असल में देश के नागरिक पर सरासर हमला नहीं है। सवाल उठना वाजिब है लेकिन इतनी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया में ऐसा होगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब लग रहा है कि एनआरसी में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है। इस मसले

आशीष, रामलाल आनंद कालेज, दिल्ली 'फिट इंडिया' अभियान

दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़ कर कुछ भी नहीं है। शरीर अगर स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। इसी कड़ी में सरकार अब आम लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए अभियान चला रही है। पहले स्वच्छता, फिर योग और अब 'फिट इंडिया अभियान'। हाल में प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान का उदघाटन करके इसकी शुरुआत की। इस अभियान का असली मकसद प्रत्येक नागरिक को दुरुस्त रखना है। इसके लिए सरकार बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी, शहर हो या गांव हर जगह लोगों को फिट रहने के तरीके बताए जाएंगे। इस अभियान में देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी शामिल किया गया है जिसके तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय को पंद्रह दिवसीय फिटनेस प्लान तैयार करना होगा और बाकायदा उसे अपने पोर्टल, वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। भारत की जीडीपी को देखें तो स्वास्थ्य पर देश में सिर्फ इसका एक फीसदी ही खर्च होता है जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। वहीं दूसरी ओर आम जीवन में लोगों का अधिकतर खर्च दवाइयों में हो रहा है। सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत के तहत वातावरण शुद्ध करने की ओर बढ़ रही है तो योग और फिट इंडिया के जरिए लोगों को भी सेहत के लिए सचेत करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में श्रीलंका, मालदीव और भूटान जैसे देश भी हमसे काफी आगे हैं। निस्संदेह यह अभियान सरकार की अच्छी पहल साबित हो सकता है।

देवपाल सिंह राणा, हापुड़।

नई दिल्ली